देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 26.08.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त स्विच सुविधा शुरू की है।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए।
- पिथौरागढ़ जिले की ग्राम पंचायत बांस मैतोली में भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन किया।
- प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक–रुक कर बारिश का दौर जारी। आठ जिलों में आज कहीं–कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट।

एकीकृत पेंशन योजना

वित्त मंत्रालय ने नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना– यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एकमुश्त एकतरफा शामिल होने की सुविधा शुरू की है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह सुविधा यूपीएस धारकों को अपनी सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के तीन महीने पहले उपलब्ध होगी।

ड्रग्स फ्री उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आज मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और अधिक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार इसमें नए पदों का सृजन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस'– 1933 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, ताकि आमजन इस पर शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभाग मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करें तथा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उस पर अमल करें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने पर बल दिया, ताकि बाहरी राज्यों से ड्रग्स की सप्लाई राज्य में न हो पाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को नशे से दूर रखने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस को रात में गश्त बढ़ाने और ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून में शीशमबाड़ा परवल रोड के निकट लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर की गई। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्राधिकरण क्षेत्र में जहां भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग की जाएगी, उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से भूमि खरीद–फरोख्त से पहले प्राधिकरण से स्वीकृति की पुष्टि अवश्य करने की अपील है।

किसान क्रेडिट कार्ड

प्रदेश में पशुपालकों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलायी जा रही है। इस योजना के तहत पशुपालक, पशुपालन से संबंधित दैनिक कार्यों के लिये व्यय कर सकते हैं। पौड़ी जिले के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत पशुपालकों को अधिकतम एक लाख 60 हजार रुपए तक की राशि उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने जिले के सभी पशुपालकों से अपील कि है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के लिये अपने निकटतम राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि कार्ड बनवाकर वे अपनी सुविधा अनुसार राशि का उपयोग कर सकते हैं। डॉ. शर्मा ने बताया कि अक्सर पशुपालकों के बीच यह भ्रांति रहती है कि कार्ड बनते ही पूरी राशि पर ब्याज देना पड़ता है, जबकि केवल उतनी ही राशि पर ब्याज देना होगा, जितनी राशि का उपयोग किया जाएगा। यानी अगर कोई पशुपालक केवल कुछ हजार रुपये ही निकालता है, तो उसे उसी पर ब्याज देना होगा।

संतृप्ति शिविर

वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पिथौरागढ़ में भारतीय स्टेट बैंक स्टेट की नकोट शाखा ने ग्राम पंचायत बांस मैतोली में संतृप्ति शिविर का आयोजन किया। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन धन व बीमा योजनाओं की जानकारी दी। शिविर का उद्देश्य जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाते खोलना, बचत खातों की पुनः केवाईसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के तहत नामांकन बढ़ाना, नामांकन अद्यतन करना और डिजिटल धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाना था। शिविर में 35 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक आने वाले दिनों में आसपास के गांवों में भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित करने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि यह आयोजन वित्तीय सेवाएं विभाग की ओर से गत पहली जुलाई से तीस सितम्बर तक प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं की संतृप्ति के लिए चलाए जा रहे तीन माह के राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है।

मौसम

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रुक–रुक कर बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय जिलों में बारिश के चलते भूस्खलन और मलब आने से डेढ़ सौ से अधिक सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए संबंधित प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, बागेश्वर जिले के मण्डलसेरा क्षेत्र के लोग इन दिनों जलभराव और क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे सात सितंबर से अनशन और चक्का जाम करेंगे। गौरतलब है कि बागेश्वर नगर से सटे मण्डलसेरा क्षेत्र में कुन्ती गदेरा और दोगाड़ गदेरा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से पानी और मलबा घरों व खेतों तक घुस गया है। पीपल चौक मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं–कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं–कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र से अति तीव्र दौर की बारिश की चेतावनी दी है।

नगर निगम रुद्रपुर

ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर नगर निगम के मेयर विकास शर्मा ने कहा है कि नगर में भोपाल की तर्ज पर तालाब विकसित किये जाएंगे। इससे वातावरण शीतल बना रहेगा और नगर में गर्मी का असर भी कम होगा। साथ ही स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की दिशा में भी भोपाल की तर्ज पर प्रयास किए जाएंगे। सरकार के निर्देश पर भोपाल और इंदौर के पांच दिवसीय एक्सपोजर विजिट से लौटे महापौर ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर नगर को स्वच्छता के मामले में देश में अग्रणी बनाने के लक्ष्य पर काम किया जाएगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी एक किसान पर अवैध खनन के आरोप में जिला खनन अधिकारी द्वारा लगाए गए एक करोड़ 91 लाख रुपये के जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्द्र और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य के खनन सचिव और न्याय सचिव न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

अधिवेशन

अल्मोड़ा में पूर्व अर्द्धसैनिक कल्याण संगठन का एक दिवसीय जिला स्तरीय अधिवेशन सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में जिले के सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स से सेवानिवृत्त अधिकारियों, सैनिकों व कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक कार्मिकों को पुरानी पेंशन देने, अर्द्धसैनिक बल के सैनिकों को शहीदों का दर्जा देने की मांग सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। संगठन के कुमाऊं डिविजन के अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने कहा अर्धसैनिक बल देश की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, उसी तरह अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए।